†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे इस प्रकार भाषण नहीं दे सकते ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक मिनट में आप को तर्क बता देता हूं । प्रधान मंत्री अपने बयान में जिम्मेदारी ओढ़ करके और फिर उस जिम्मेदारी से छटक जाया करते हैं । सवाल जवाब के बिना प्रधान मंत्री का बयान . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह औचित्य प्रश्न नहीं है । यह सभा की इच्छा है कि वे यह वक्तव्य दें । प्रधान मंत्री ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आपके इस तरह से चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा । मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं . . .

श्री बागड़ी : औचित्य प्रश्न . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें ।

†**डा० राम मनोहर लोहिया** : मेरा तर्क सुन लीजिये . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । आप बैठ जाइये । आपके नेता ने प्रश्न उठाया है और मैंने विनिर्णय दे दिया है ।

श्री बागड़ी : कालिंग एटेंशन नहीं हो सकता है, एडजर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता है वोट आफ नो-कान्फिडेंस से पहले, तो इनके बयान की क्या जरूरत है ।

भारत-चीन सीमा पर चीनी सेनाओं के जमाव के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : २३ जनवरी १९६३ को मैंने आठ नम्बर का एक श्वेत-पत्र आपके सामने रखा था ; इसमें भारत और चीन लोक गणराज्य की सरकारों द्वारा एक-दूसरे को भेजे गए पत्र, ज्ञापन और टिप्पणियां सम्मिलित थीं । उसके बाद और भी बहुत से पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है । मैं सदन की मेज पर श्वेत-पत्र नं० ९ रख रहा हूं जिसमें वे टिप्पणियां ज्ञापन, और पत्र हैं जो जनवरी और जुलाई १९६३ के बीच भारत और चीन की सरकारों ने एक-दूसरे को भेजे हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० १४१५/६३]**

पिछली बार सात मई को जब मैंने भारत-चीन संघर्ष के बारे में बयान दिया था तब मैंने भारत सरकार के ३ अप्रैल के पत्र की प्रतिलिपियां भी सदन की मेज पर रखी थीं जिसमें मैंने भारत-चीन सीमा मतभेदों पर समझौता करने के लिए कई ठोस सुझाव दिए थे । मैंने उस पत्र की प्रतिलिपियां भी रखी थीं जो मैंने १ मई को प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई को लिखा था और जिसमें मैंने चीन के भारी हमले के बाद के पिछले कुछ महीनों की घटनाओं की समीक्षा की थी और चीन के साथ अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त की थी तथा उन ठोस सुझावों की भी चर्चा की थी जो कि हमने दिए थे । चीन लोक गणराज्य की सरकार ने इन पत्रों का अब तक जवाब नहीं दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन ने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के हमारे उन ठोस सुझावों का कोई जवाब तो दिया नहीं उल्टे उस के बाद से भारत-चीन सीमा पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनसे हमें चिंता ही गई है। चीन सरकार ने कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों के प्रति जो नकारात्मक और प्रतिकूल रवैया अपनाया वह सदन को याद होगा। कोलम्बो प्रस्तावों की तनिक भी परवाह किए बगैर चीनियों ने अपनी इकतरफा लड़ाईबंदी और वापसी की तथाकथित घोषणा पर अमल करना शुरू कर दिया और तीनों क्षेत्रों के सेनारहित इलाकों में २६ असैनिक चौकियों की स्थापना कर दी ; जाहिरा तौर पर यह दिखाने के लिए कि वे "सीमा पर रहने वालों के सामान्य आवागमन के लिए, तोड़-फोड़ करने वालों की कार्रवाईयां रोकने और सीमा पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं।" ऐसी तथाकथित सात असैनिक चौकियां इकतरफा निर्णय पर पश्चिमी क्षेत्र के सेनारहित इलाके में बनाई गईं ; और इस प्रकार उस कोलम्बो प्रस्ताव की अवहेलना की गई जिसमें यह कहा गया था कि इस सेनारहित इलाके में दोनों पक्षों की असैनिक चौकियां होनी चाहिएं। चीनियों के इकतरफा एलान के मुताबिक ही पूर्वी क्षेत्र के सेना रहित इलाके में उन्हें १६ असैनिक चौकियां स्थापित करनी थीं ; लेकिन आज वहां सैनिकों और असैनिकों की मिली-जुली ५२ चौकियां हैं और अब तो यह दिखावा भी खत्म कर दिया गया हैं कि यह चौकियां असैनिक है। इन चौकियों के अलावा सीमा पर, खासकर पूर्वी क्षेत्र में चीनियों की ओर से खोज और गश्त की काफी कार्रवाई हो रही हैं।

जहां तक हमारा संबंध है, भारत सरकार ने कोलम्बो प्रस्तावों का ईमानदारी से पालन ही नहीं किया बल्कि चीन के इकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के अमल और सैनिकों की वापसी के काम में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं लगाई है। हमने यह उम्मीद की थी कि कोलम्बो सम्मेलन के देशों की मित्रतापूर्ण सलाह का अच्छा असर होगा और चीनी कोलम्बो प्रस्तावों को मान लेंगे। हमने उम्मीद की थी कि जो भी हो वे अपनी इकतरफ़ा घोषणा पर तो अमल करेंगे ही। हमारी यह आशा भी गलत सिद्ध हुई है क्योंकि चीन ने केवल कोलम्बो प्रस्तावों का उल्लंघन किया हैं बल्कि सेना रहित क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिक चौकियां क़ायम कर तथा सीमा क्षेत्रों में आक्रमक ढंग से खोज और गश्त की कार्रवाई शुरू कर अपने इकतरफा एलान को भी भंग किया है।

अंत यहीं नहीं होता। वे तिब्बत में और सेना ले आए हैं और उन्होंने सीमा पर भी अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ा दी है। हमारी सीमा पर चीनी फ़ौजों की संख्या आज उस से भी कहीं ज्यादा है जितनी कि अक्तूबर १९६२ में थी जब कि उन्होंने हमारे ऊपर अकारण भारी हमला किया था। चीन की फ़ौजी ताकत में वृद्धि के अलावा एक और बात यह हुई है कि उन की फ़ौजें भारत सीमा के पास अपने मजबूत अड्डों और कैम्पों में इतनी आगे आ गई हैं जितनी कि पिछले अक्तूबर में भी नहीं आई थीं। पिछले कुछ महीनों में भारतीय सीमा के पास काफी संख्या में बैरकें बनाई गई हैं, तोपों के आधार-स्थान बनाए गए हैं, सामान रखने की जगह बनाई गई हैं। और हवाई-अड्डे बनाए गए हैं। इन सीमा क्षेत्रों में बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं, ज़मीन के नीचे टेलीफोन की लाइनें बिछाई गई हैं, और एक दूसरे को मिलाने वाली खाइयां खोदी गई हैं। चीन द्वारा भारतीय इलाके और भारतीय वायुक्षेत्र के अतिक्रमणों की संख्या भी बढ़ी हैं, खास कर पिछले कुछ महीनों में।

इन सब कार्रवाइयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की उत्तरी सीमा के निकट बराबर बनाए रखने के ख्याल से चीनी वहां अपनी स्थिति मजबत कर रहे हैं। यह भी हो सकता हैं कि वे आगे के इन अड्डों से जहां कि उन्होंने अपनी स्थिति मज़बत कर रखी है, भारत पर एक बार फिर आक्रमण करने की बात सोच रहे हों।

चीनियों की मंशा क्या है, यह जानना मुश्किल है। लेकिन इतनी बात तो साफ़ है कि वे हमारे मित्र नहीं हैं। हमें पता चला हैं कि १७ जुलाई, को चीन सरकार ने कोलम्बो सम्मेलन में भाग लेने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वाले देशों के मिशनों के प्रधानों को पेंकिंग में एक ज्ञापन पेश किया था जिस में भारत द्वारा तथाकथित उत्तेजनापूर्ण सैनिक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी। हो सकता है कि पहले की ही तरह यह भी "आत्मरक्षा में प्रत्याक्रमणों" के व्यापक आधार पर, भारत पर नए आक्रमण को उचित ठहराने की एक चाल हो। हमने अपनी सीमा पर चीन की नई आक्रामक गतिविधियों से कोलम्बो सम्मेलन के देशों की सरकारों को अवगत करा दिया है।

चीन का उद्धत और आक्रामक रवैया हाल ही के महीनों में सिर्फ़ भारत-चीन संबंधों के बारे में ही स्पष्ट नहीं हो गया है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यापक क्षेत्र में स्पष्ट हुआ है। हाल ही में परमाणु परीक्षणों पर आंशिक प्रतिबंध लगाने की संधि हुई उस के प्रति चीन का रवैया इस का साक्षी है। संसार के प्रायः सभी देशों और जातियों ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने तथा विश्वशांति और निरस्त्रीकरण के उपायों की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण क़दम कहा है।

हम आशा करते हैं कि सुमति की विजय होगी और चीन शांति के पथ पर लौट आयेगा। हम चीन के साथ सीमा संबंधी मतभेदों का शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यावहारिक क़दम उठाने की दिशा में हमने बार-बार रचनात्मक सुझाव दिये हैं। फिर भी, चीनी अधिकारियों में न सिर्फ इन की उपेक्षा की है बल्कि हमारी सीमा पर अपनी हमलावर तैयारियां और तेज कर दी हैं। पिछले अक्तूबर-नवम्बर हम पर आक्रमण जो भारी हमला किया गया था उसको देखते हुए हमें इन आक्रामक कार्रवाईयों पर नज़र रखनी होगी, परिस्थितियों का सामना करना होगा, और शांत तथा दृढ़ रह कर अपनी रक्षा की तैयारियां बढ़ानी होंगी ताकि अगर हमारी प्रादेशिक अखंडता पर फिर कोई खतरा आए तो हम उस का मुक़ाबला कर सकें

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : स्पष्टीकरण के लिए एक प्रश्न है। क्या प्रधान मंत्री स्पष्ट शब्दों में आश्वासन देते हैं कि चीनियों के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाएं पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह तैयार हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : निस्संदेह वे अधिक अच्छी तरह तैयार हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : उन्होंने कहा है कि हमें चीनियों द्वारा और अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिये। क्या वे अपना इलाका खाली करवाने के लिए कोलम्बो प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से पता लगता है कि चीन द्वारा आक्रमण की संभावना है और उस ने पूर्वी क्षेत्र में सैनिक एवं असैनिक ५१ चौकियां बना ली हैं जब कि वहां हमारी चौकियां नहीं हैं। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हम किस प्रकार असम और पूर्वोत्तर सीमा की रक्षा करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह नहीं बता सकता कि हमें सैनाएं कहां रखनी चाहियें। यह निर्णय प्रतिरक्षा सलाहकारों और सैनिक अधिकारियों को करना है। निस्संदेह हम असम और नेफा की रक्षा करेंगे।

मैं श्वेत पत्र संख्या ९ के अतिरिक्त चाऊ-एन-लाई के २ अगस्त के पत्र और उस पर मेरे १४ अगस्त के उत्तर की प्रतियां भी रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **हरि विष्णु कामत** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या हमारी सेनाएं बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए अधिक तैयार हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । प्रधान मंत्री ने ही सभा में ही बताया था कि नेफा में सेनाएं न भेजना सैनिक और राजनैतिक दोनों दृष्टि से किये गये निर्णय के अनुसार है । तो क्या वे नेफा की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैंने अध्यक्ष महोदय और प्रधान मंत्री को भी लिखा था कि जस्टिस दास का प्रतिवेदन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व सभा पटल पर रखना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि सब वक्तव्य दिये जाने के उपरांत प्रतिवेदन रखा जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका निर्णय सरकार को करना है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यह प्रतिवेदन कब रखा जा रहा है ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : आप ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को सलाह या निवेदन दे सकते हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : अध्यक्ष महोदय ने इस का आश्वासन दिया था कि वे प्रधान मंत्री को लिखेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान् मेरा विचार है कि मैं श्री जस्टिस दास के प्रतिवेदन के बारे में एक वक्तव्य दूंगा । किन्तु जैसा मैं ने पहले बताया है मैं प्रतिवेदन पटल पर नहीं रख सकता । मैं ने पुन: मुख्य न्यायाधिपति और जस्टिस दास से परामर्श किया है । वे इसे सभा पटल पर रखने के लिए सहमत नहीं थे । वे कहते हैं कि इस का कुछ भाग रख दिया जाय । किन्तु इस के महत्वपूर्ण भाग को सभा पटल पर न रखना अनुचित होगा । मैं इस पर कल वक्तव्य दूंगा ।

†**श्री नाथ पाई** : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : जब इस विषय का उल्लेख संसद् में किया गया था और यह जांच प्रधान मंत्री द्वारा संसद् में की गई घोषणा के अनुसरण में की गई थी तो यह संसद् का विशेषाधिकार है कि सारा प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाय । सम्बन्धित मंत्री और संसद् के लिए भी यही उचित है कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाय । संसद् सर्वोच्च निकाय है । प्रधान मंत्री का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि यह प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं श्री मुकर्जी के तर्कों से असहमत हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । देश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है । अत: हमें ठीक ठीक स्थिति का पता होना चाहिये ।

†**श्री रंगा** : सभा को बताया गया था कि नेफा में हुई घटनाओं की जांच की जायगी । जेनरल हंडरसन ने प्रतिवेदन भी दे दिया हैं । हम आशा करते हैं कि वह प्रतिवेदन कम से कम सोमवार को सभा पटल पर रखा जायगा ताकि अविश्वास प्रस्ताव में उस पर चर्चा की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आलोचना कर सकते हैं किन्तु यह निर्णय सरकार को करना है । मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री का जो स्टेटमेंट था उस में यही कहा गया है कि हमला हो सकता है और उस के लिए देश को तैयार रहना चाहिए । सरकार तैयारी कर रही है, हमले का सामना करने के लिए तैयारी हो वह तो ठीक है लेकिन मान लो कि हमला न हो तो क्या प्रधान मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस भारतीय भमि पर अभी विदेशियों का कब्जा है, जो हमारे देश की भूमि अनुचित तौर पर शत्रु के कब्जे में है उस के लिए क्या तैयारी है और क्या अपनी छीनी गई भूमि की फिर से वापिस लेने की हम तैयारी कर रहे हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति शांति ।

श्री रामसेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दास कमिशन की नियुक्ति हुई तो प्रधान मंत्री जी ने यह कैसे उन्हें वचन दे दिया कि उन का जी इस पर प्रतिवेदन होगा उसे सदन पटल पर नहीं रक्खा जायेगा । उन्हों ने आखिर ऐसा क्यों कहा ? इनक्वायरी कमिशन बिठाने का मतलब होता है कि उस के द्वारा जांच हो और उस को रिपोर्ट सदन की टेबुल पर रक्खी जाय ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को मैं समझता हूं यह याद होगा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने और जांच करवाना इस शर्त्त पर मंजूर किया था कि उन की रिपोर्ट पेश न की जाय । वह रिपोर्ट पार्लियामेंट में रक्खी न जाय और न पबलिश की जाय । यह उन्हों ने कहा था । इस को बाबत मैं ने पार्लियामैंट में कह दिया था । अभी कोई २, ३ या ४ हफ्ते हुए मैं ने उन से इस बारे में फिर सलाह की और उन की राय पूछी । वे अभी भी अपनी उसी पुरानी राय पर क़ायम है । उन्हों ने कहा कि वह रिपोर्ट पबलिश करना और पार्लियामेंट में पेश करना नामुनासिब बात होगी और एक ग़लत प्रीसीडेंट क़ायम करना होगा । क्योंकि यह एक स्टैचुटरी इनक्वायरी नहीं थी । यह दूसरे क़िस्म की है । इस में न जज प्रोटैक्टेड हैं और न और लोग । ऐसी रिपोर्ट हमेशा प्राइवेट ही होती है । चीफ़ जस्टिस ने अपनी पुरानी राय दुहराई कि इसे पबलिश करना या पार्लियामेंट में पेश करना मुनासिब न होगा ।

अब मैं प्रोफेसर रंगा के प्वाएंट का जवाब देता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : जब यह रिपोर्ट किसी के सामने और सदन के सामने आयेगी नहीं तो वह है किस काम की ?

श्री रामसेवक यादव : अभी प्रधान मंत्री जी ने जो कहा उस के सम्बन्ध में मैं एक चीज़ की जानकारी चाहता हूं । जब प्रधान मंत्री जी स्वयं समझते हैं कि उस प्रतिवेदन को आना चाहिए । उस को पेश न करना और पबलिश न करना ठीक नहीं है तो प्रधान मंत्री जी ने कैसे इस शर्त्त पर इस क्वायरी कमेटी नियुक्त करना मान लिया ?

श्री बागड़ी : कहीं राज़ यह तो नहीं है कि कुछ और मंत्री लपेट में न आ जायें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री रंगा ने जिस जांच की बात की है, वह जांच हो चुकी है और चीफ आफ आर्मी स्टाफ ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, उस का संक्षेप प्रतिरक्षा मंत्री के पास है । प्रतिरक्षा मंत्री इस बारे में अपना वक्तव्य देंगे । वैसे उन का विचार है कि इस प्रकार के प्रतिवेदन को संसद् में प्रस्तुत कर के प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये । मैं उन के इस विचार से

†मूल अंग्रेजी में

पूर्णतः सहमत हूं। इस प्रकार के प्रतिवेदनों को छाप देने से हमारी सैनिक तैयारी में बाधा पड़ सकती है।

†**श्री नाथ पाई :** आश्चर्य है कि प्रतिरक्षा मंत्री को भी केवल प्रतिवेदन का संक्षेप ही दिया गया। यद्यपि प्रतिवेदन का सम्बन्ध तो पुरानी बातों से है, नई तैयारियों से नहीं। हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या बात गलत हुई और उस के लिए कौन उत्तरदायी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे विचार में हमारी सेना लोग और हमारे प्रतिरक्षा मंत्री, माननीय सदस्य से स्थिति को बेहतर समझते हैं। . . . (**अन्तर्बाधायें**)।

†**श्री रंगा :** प्रतिरक्षा मंत्री को इस बारे में शीघ्र ही वक्तव्य देना चाहिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे विचार में वक्तव्य को तैयार करते कुछ दिन लग जायेंगे। काफी सोच समझ कर वक्तव्य तैयार करना होगा। सारे कागज तो अभी तक मैं ने भी नहीं देखे।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रधान मंत्री महोदय को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के अपमान के इस मामले का उल्लेख अविश्वास के प्रस्ताव के समय होना बड़ा जरूरी है। यह प्रस्ताव सोमवार को आ रहा है। क्यों नेफा में सब गड़बड़ हुई। यदि सारे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना सम्भव न हो तो अपने कुछ परिणामों को तो सभा पटल पर रखा ही जा सकता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं यह माननीय सदस्य को इच्छा प्रतिरक्षा मंत्री को बता दूंगा परन्तु सोमवार तक तो यह तैयार नहीं हो सकती। ठीक है अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है, परन्तु हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जिस से हमारी प्रतिरक्षा के काम में कोई रुकावट पैदा हो। हमें आर्मी स्टाफ और प्रतिरक्षा मंत्रालय की राय को इन मामलों में महत्व देना ही होता है।

†**श्री नाथ पाई :** आप इस मामले में संसद् के प्राधिकार की उपेक्षा कर रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं यह नहीं समझ पाया कि उन गोपनीय बातों को बताने से ही संसद् के प्राधिकार की रक्षा होती है जिस से देश को हानि पहुंचती हो।

†**श्री नाथ पाई :** यह गोपनीय बातें नहीं हैं, सारी दुनिया को उस का पता है। आखिरकार इस सदन के भी कुछ विशेषाधिकार हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ। क्यों वहां यह सब गड़बड़ हुई। हम यह किसी बदले की भावना से नहीं पूछ रहे, देश के हित में पूछ रहे हैं। स्वयं प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि जोकि नेफा में हुआ हैं उस की पूरी सविस्तार जांच होगी। पता लगाया जायेगा कि क्यों यह सब कुछ हुआ और फिर संसद् को बताया जायेगा। यह आश्वासन प्रधान मंत्री द्वारा संसद को दिया गया था। इस मामले का हमारी भविष्य की तैयारियों के साथ कोई सम्बंध नहीं। यह तो भूत को बातों के बारे में है। प्रधान मंत्री यह भी बताना नहीं चाहते कि इस प्रतिवेदन के परिणाम क्या थे ?

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशितः आंग्ल भारतीय) : मेरा प्रधान मंत्री से यह निवेदन है कि वह प्रतिवदन के वे अंश न बतायें जो कि उचित न हो। परन्तु उन्हें कुछ भ्रांतियां अवश्य दूर कर देनी चाहिएं। यह कि चौनियों पर गोली न चलाने के आदेश दिल्ली से गये थे। सेनापतियों को अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने में रुकावटें डाली गयी। ये भ्रांतियां आप को दूर करनी चाहिएं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सब निराधार बातें हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : ठीक है, प्रधान मंत्री जो कहते है कि ये आरोप निराधार है । परन्तु हमें पूरी तरह, निश्चिय ढंग से यह बता दिया जाय कि ये सब अफवायें निराधार हैं । तो यह सरकार के ही हित की बात है । उससे और अफवायें फैलने का कोई कारण नहीं रहेगा । हम सब आज भी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि १६,००० व्यक्ति चीनियों पर एक उंगली भी नहीं उठा सके । इसीलिए हम सब बातें जानना चाहते हैं । निश्चित रूप से ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सैनिक तैयारी के अलावा मन की कमजोरी उपूसी में हार का कारण रही है । बोमदीला, वालोंग, दरांग के पतन के समय, मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक सर्क्यूलर यहां से नहीं गया था जिस में यह लिखा हुआ था कि अगर किसी जगह का पतन शुरू होने वाला हो तो उस को खाली कर दो ? इस का क्या अर्थ था ? मैं जानता हूं कि बोमदीला में एक गोली नहीं चली फिर भी वह खाली कर दिया गया । यहां से एक सर्क्यूलर गया था कि खाली करो उस जगह को जो जल्दी गिरने वाली हो । अब मन की कमजोरी की वजह से खाली रात को कुछ हुल्लड़ सुनने के सबब से उस जगह को खाली कर दिया गया । तो इस के लिए क्या तैयारी हो रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो क्वश्चन अवर को बढ़ाना है कि मैं जबाब दूं इस सवाल का । यह क्या सिलसिला है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : बढ़ाना, यह शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए । प्रधान मंत्री नौकर हैं, सदन मालिक है । मालिक के साथ नौकर को जरा अच्छी तरह से बात करना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर बहुत से प्रश्न हो चुके हैं । सोमवार को जो बहस होगी उस में यह बातें उठाई जा सकती हैं ।

श्री भगवत झा आजाद : वह नौकर हैं तो आप चपरासी हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मंजर करूंगा । जाइए और बनिए उन के.....चपरासी । ऐसे ऐसे नौकरों को इक्ट्ठा कर रखा है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : डा० लोहिया आपे से बाहर हो गये हैं । जरा उन को थामने की कोशिश कीजिए । ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो आम तौर से इस सदन में नहीं कही जातीं । उनको आदत नहीं है । नए आदमी आए हैं । आप उन्हें सिखा दीजिए कि यहां कैसे बरताव होता है ।

श्री प्रिय गुप्त : श्री नेहरू विशिष्ट सदस्य हैं । उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वह ऐसी बातें कहें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी आदत आप को डालनी पड़ेगी ।

श्री बागड़ी : नए पुराने का सवाल नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

---

†मूल अंग्रेजी में